influencing the course of world events. NAM - will lose any significance it has. I want to know whether the External Affairg Minister considers that NAM fees that objective in view, apart from limited /economic co-operation; and if that objective is there whether some aort of headquarters would be celled for.

MR. CHAIRMAN: The question of headquarters is out.

SHRI P. V. NARASIMHA RAO. I have already stated the position. An evewhehning majority of the countries m the Movement are against having a headquarters. Now, how would it be desirable for India to fly in the face of this overwhelming opinion? (Interruptions) That is why several bodies are beinig set up. And I may also inform the hon. Member that it is not amorphous, its wprk ig not being diffused. Its work is being done quite adequately and systematically through the Co-ordinating Bureau. Various meetings are taking place. The Co-ordinating Bureau meet at Foreign Ministers' level several times between Summits. So we afte Un touclhi, and we are grappling with all the problem$_a$ that are facing us.

"" PROF. SOURENDRA BHATTA-CHARJEE: Sir, one more question.

MR. CHAIRMAN: No. Question No. 443.

गावों में खेल सुविधायें प्रदान करना

*443. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव**: क्या **खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार देश में खेलों के स्तर को बनाए रखने और उसे ऊंचा उठाने के लिए क्या विशेष प्रबन्ध कर रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि गांवों में आवश्यक साज सामान, प्रशिक्षण और पौष्टिक आहार की कमी है यद्यपि दौड़ना, तैरना, कुश्ती, तीरन्दाजी आदि उनके स्वाभाविक गुण हैं ; और

(ग) क्या सरकार गांवों में उक्त सुविधायें प्रदान करने का विचार रखती है ; यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या योजनायें हैं ?

संसदीय कार्य, खेल और निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (ग) सरकार को गांवों में खेल-कूद, कुश्ती इत्यादि में विद्यमान अंतरनिहित खेल प्रतिभा की जानकारी है। सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक अवस्थापन और प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता की भी जानकारी है।

2. खेल एक राज्य विषय होने के नाते, खेल स्तरों में सुधार और उसे बनाए रखने के लिए, न केवल गांवो में अपितु शहरी क्षेत्रों में भी आवश्यक अवस्थापना और प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि इस दिशा में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता देने के दृष्टिकोण से, केन्द्रीय सरकार अपनी संवैधानिक और वित्तीय सीमाओं के अन्तर्गत कई निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है :—

(i) ग्रामीण खेल केन्द्र स्थापित करने, वार्षिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने, खेल मैदानों के विकास, गैर-खर्चीले किस्म के खेल उपस्करों की खरीद,

स्टेडियमों तरणतालों खेल परिसरों के निर्माण आदि के लिए राज्य खेल परिषदों/राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।

(ii) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला के माध्यम से प्रति वर्ष खेलों में देश भर के प्रतिभाशाली स्कूली छात्रों को प्रति वर्ष 600 रु० की राशि की 800 राज्य स्तरीय छात्रवृत्तियों और प्रति वर्ष 900 रु० की राशि की 400 राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्तियों प्रदान की जाती हैं ।

(iii) नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला के माध्यम से प्रति वर्ष खेलों में देश भर के प्रतिभाशाली छात्रों को प्रतिवर्ष 1200 रू0 की राशि की 100 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है ।

(iv) कालेजों और विश्वविद्यालयों में खेलों की प्रगति, खेल मैदानों के विकास, व्यायाम शालाओं के निर्माण और विश्वविद्यालयों स्तर के प्रशिक्षण शिविरों, संयुक्त विश्वविद्यालय शिविरों के आयोजन और अंतर-विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय विश्वविद्यालयों की एसोशिएशन के माध्यम से वित्तीय सहायता ।

(v) राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष ग्रामीण खेल टूर्नामेंट आयोजित करने और ऐसे टूर्नामेंटों को ब्लाक, जिला और राज्य स्तरों पर आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देना ।

(vi) महिलाओं के लिए वार्षिक राष्ट्रीय खेल समारोह आयोजित करना और राज्य सरकारों को ब्लाक, जिला और राज्य स्तरों पर महिला खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए सहायता देना ।

(vii) राष्ट्रीय खेल संघों/एसोशिएशनों को प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने, विदेश जाने वाली टीमों के यात्राखर्च के लिए अनुदान, भारत आने वाली विदेशी टीमों राष्ट्रीय चम्पियनशिप सहायक सचिवों, के लिए वेतन, खेल उपस्कर खरीदने आदि के लिए वित्तीय सहायता ।

(viii) उत्कृष्ट पुरुष खिलाड़ियों एवं महिला खिलाड़ियों को प्रत्येक वर्ष उनके खेल निष्पादन के आधार पर अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं । प्रत्येक पुरस्कार-ग्राही को 2 वर्ष की अवधि के लिए 200 रू0 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ।

(ix) ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत के खेलों का आयोजन करना देश के विभिन्न जिलों में कार्यरत 194 नेहरू युवक केन्द्रों के कार्यकलापों में से एक है । प्रत्येक नेहरू युवक केन्द्र को न केवल धनराशि दी जाती है अपितु इसके खेल कार्यकलापों के लिए एक प्रशिक्षित प्रशिक्षक की भी व्यवस्था की जाती है ।

3. सामान्यतः खेल स्तर को बढ़ाने के तकनीकी पहलू का ध्यान रखने के लिए, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियला (भारत सरकार द्वारा स्थापित) आवश्यक कार्रवाई करता है । इसने दो क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए हैं । अर्थात एक कलकत्ता में, और दूसरा बंगलौर में । इसने 1961 से अपने प्रारंभ होने से ही विभिन्न विषयों में 5850 व्यावसायिक प्रशिक्षक

प्रशिक्षित किए हैं। संस्थान द्वारा, अपने गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के अतिरिक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को प्रशिक्षकों की सेवाओं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। यह संस्थान तकनीकी रूप से सुसज्जित है, और इसमें प्रशिक्षण और खिलाड़ी पुरूषों और महिलाओं के चयन को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए, एक खेल विज्ञान संकाय भी उपलब्ध है।

4. सरकार ने खेल विकास प्राधिकरण को स्थापित करने का निर्णय लिया है जिसके कार्यकलापों में खेलों के विकास स्टेडियमों इत्यादि के रख-रखाव और उनकी उपयोगिता को शामिल करने का विचार है।

5. राज्य सरकारों और खेलों के विकास से संबंधित अन्य निकायों के लिए एक स्वीकृत नीति ढांचा जिसके फलस्वरूप वे सभी पहलुओं से खेलों के विकास के लिए ठोस कदम उठा सकते हैं, की व्यवस्था करने को ध्यान में रख कर सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से, राष्ट्रीय खेल नीति पर एक संकल्प पारित करने पर विचार कर रही है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या अखिल भारतीय खेल परिषद् ने बंगलौर की अपनी बैठक में सरकार को कुछ सुझाव दिये हैं? उनमें मुख्य सुझाव है कि खेलों को प्रगति के लिये राष्ट्रीय आय का 1 प्रतिशत खर्च किया जाए। एक तो सरकार को यह निश्चित करना है। बिना इसको निश्चित किये खलों का जो विकास चाहते हैं वह शब्दों तक रह जाता है, खेलों में नहीं रहता। इसके साथ इसमें और भी सजेशन्स दिये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इसको कहां तक कार्यान्वित करना चाहती है राज्य सरकारों से मिलकर—खेल और फिजिकल एजूकेशन को स्कूल और कालेजों में अनिवार्य करना, प्रतियोगिताओं को प्रश्रय देना, खेल के साधन की उपलब्धता, खेल के उद्योगों को बढ़ावा, खिलाड़ियों को सुविधा नौकरी में, बीमा में और पेंशन में, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन-पुरस्कार, स्कालरशिप, खिलाड़ियों की पहचान विशेष कर गांवों में, खेल के संस्थान का संगठन, खेल मैदानों को कायम रखना और बढ़ाना। खेल के क्षेत्र में अनुसंधान की स्थिति को अभी तक ठीक नहीं किया गया और मैं समझता हूं कि इसी कारण खेल पर जो 70 करोड़ लोगों का वर्चस्व होना चाहिए वह नहीं हुआ है। इसी के साथ जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है। इन सारे खेलों की व्यवस्था होते हुये यह ध्यान रखना चाहिए कि भारतवर्ष एक पौराणिक राष्ट्र है, उसके अपने खेल हैं जैसे पहले पहलवानी का खेल हिन्दुस्तान का जगत विख्यात था, लेकिन जमींदारी न रहने के कारण पहलवानों के भोजन की व्यवस्था नहीं हुई और उनका अखाड़ा समाप्त हो गया। उस को रिवाइव करने का प्रयास नहीं हुआ। इसी तरह से कबड्डी का खेल है, और भी अनेक दर्जनों, भारत के खेल हैं जिनको सरकार विदेशी खलों के सामने प्रश्रय नहीं दे रही है। क्या सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन कर इन खेलों को भी अपनायेगी जिससे भारत का वर्चस्व फिर खेल के मैदान में हो?

श्री बूटा सिंह : सभापति जी, आल इंडिया कौंसिल आफ स्पोर्ट्स ने अपनी मीटिंग में, जो 10 अगस्त को हुई, मशवरा दिया है जिसके तहत इस वक्त खेलकूद के लिये जो राशि निर्धारित की जा रही है उस में कुछ वृद्धि करने का

प्रस्ताव है। यह खेल कूद का जो विषय है यह राज्य सरकारों का विषय है। हम इस में बहुत थोड़ा मदद कर सकते हैं, परन्तु जो भी इस वक्त की परिस्थिति है उसके बारे में मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं। इस वक्त जो प्रोग्राम चल रहे हैं उन में :—

(i) For holding of annual coach ing camps at the State level, 50 per cent of the approved expendi ture on camps subject to a ceiling *of Rs.* 50,000 per year for a State j and Rs. 20;000 per year for a Union Territory.

I

(ii) For establishment |mainten-anfce oj Rural Sports Centres, 50 per cent of the total expenditure subject to a maximum of Rs. 300 per annum per centre for ho-norarium to teachers in charge of the centres, and Rs. 300 per centre Jor sports equipment in the flrst year and Rs. 150 per centre per annum in subsequent years,

(iii) For purchase of sports equipment of non-expenditure nature, 75 per cent of the cost, subject to a maximum of Rs. 50,000 in the entire 6th Plan period, to any State .or Unlion Territory.

(iv) For development of play-fields, Rs. 20.000 or 50 per cent of the cost per play field; whichever is less. For hilly areas the quantum of Central grant is Rs. 20;000 or 75 per cent of the cost, whichever is less.

(v) (a) For construction of utility stadia, swimminig pools and indoor stadia, Rs. 1,00,000 or 50 per cent of the cost, whichever is less, in planes, and Rs. 2,50,000 or 75 per cent of the cost, whichever is less, in hilly areas.

(to) For flood-lighting of playgrounds, Rs. 25,000 or 50 per cent of the expenditure, whichever is less.

The playflelds, stadia, swimming pools may be located in rural or urban areas, according to the preference of the State Governmemte concerned.

(vi) Construction of composite stadia j sports complexes; Rs. 5 Iakhs or 25 per cent of the cost of the projects, whichever is less.

This is the present arrangement. In its meeting on the 10th of August, the All India Council of, Sports recommended upward revision of these ceilings. This is receiving the attention of the Government of India and we hope that with the support from various States and also with the approval of the Government of India, we can do it. We would welcome any suggestion which will increase the allocation fo r the development of sports in the country.

Sir, the hon. jMember ha,s asked about the indigenous games. I wish to inform the hon. Member and tbe House that already there is a draft national policy for the sports and games in the country, which is receiving the attention of our Department. We are meeting the Ministers in charge of Sports from various States on the Ist of September. That policy will be discussed with them. The Consultative Committee of the Department of Sports has already gone through it and made some valu-able suggestions. We hope that after we have put it to the State Governments which are to'implement the policy, we will be able to come back to this hon. House with a solid national policy for the development of sports and games.

माननीय सदस्य ने जो कुछ हमारे भारतीय खेल हैं जैसे कबड्डी है, खोखो है, कुश्ती है या आर्चरी है उसके बारे में कहा। इनके जो नेशनल टूरनामेंट्स नैशनल लेविल पर हैं उन को हम ने कैटेगेराइज किया है। ग्रुप एक में कबड्डी

खोखो, आर्चरी और रेसलिंग है। ग्रुप दो में एथलेटिक्स, हाकी और बास्केट बाल है, ग्रुप तीन में वालीबाल और फुटबाल हैं और ग्रुप चार मे जमनास्टिक हैं और ग्रुप 5 मे स्विमिंग है। यह सब खेल उस में शामिल हैं और इन की बढ़ोत्तरी के लिये और इनके विकास के लिये सरकार बहुत सक्रिय है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : दूसरा प्रश्न पूछने के पहले मैं जानना चाहता हूं कि मैंने यह कहा था कि खिलाड़ियों को नौकरी में, पेंशन में, बीमा में और उन को अच्छा भोजन देने में जो आवश्यक सुविधायें देने की बात थी उनके बारे में आपने कोई विचार प्रकट नहीं किये। दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि आर्चरी में हमारे जितने बनवासी हैं वह सिद्धहस्त हैं लेकिन उनका इक्विपमेंट जो है वह आज के आधुनिक इक्विपमेंट के मुकाबले का नहीं है और इस लिये वे केवल 15, 20 मीटर से ज्यादा दूरी तक अपने बाण नहीं फेंक सकते जबकि आधुनिक धनुष से 50, 60 मीटर तक वाण फेंका जा सकता है। ऐसे ही नदी के किनारे रहने वाले लोग तैराकी में प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते कि उनको पूरी सुविधायें और जानकारी हो। आपने जितना वर्णन हमको दिया है वह बहुत पर्याप्त है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि सुभाषचन्द्र बोस राष्ट्रीय संस्थान पटियाला में आज अकेला है। वह क्या 70 करोड़ लोगों के बच्चों और खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और प्रशिक्षण के लिये पर्याप्त है? क्या आप विचार करेंगे कि ऐसे संस्थान हिंदुस्तान में और चार, पांच अन्य भागों में भी होने चाहिए?

श्री बूटा सिंह : सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो पहले प्रश्न में दो, तीन मुद्दे रखे थे जैसे नौकरी, पेंशन और बीमा और खिलाड़ियों के लिये अच्छे भोजन की व्यवस्था के बारे में, उस में जो पहले तीन मुद्दे हैं नौकरी, पेंशन और बीमा के यह तो सीधे हमारे मन्त्रालय से संबंध नहीं रखते हैं। परन्तु इन पर विचार होना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर कि अच्छे खिलाड़ियों के लिये जिन्होंने हिन्दुस्तान के लिये नाम पैदा किया है, और गोल्ड मेडल जीते हैं उन को आल इंडिया सर्विसेज में किस तरह से लिया जाय ताकि उन का हौंसला बढ़े या उन के लिये कुछ स्थानों की सुरक्षा हो या उनके लिये कुछ और आसानियां रख दी जायें कि जो नेशनल चैम्पियन्स हैं उनको कुछ अतिरिक्त सुविधायें दी जायें इसके बारे में सुझाव रखा जा सकता है और माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है वह मैं दूसरे संबंधित मंत्रालयों को जरूर लिखूंगा। पेंशन और बीमा की खास कर खिलाड़ियों के लिये अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। भोजन के बारे में जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया तो जब तक कोई खिलाड़ी हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट आफ सपोर्ट्स, पटियाला में रहता है तब तक उस को भोजन का जो स्टैंडर्ड है जिसकी साइंटिफिक अनालिसिस कर के सिफारिश की गयी है कि इतना भोजन उनको चाहिए वह उन को दिया जाता है और उसमें हमने पिछले वर्ष जरूर बढ़ोत्तरी की है और उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया है और जहां कहीं भी कोचिंग कैंप्स या ट्रेनिंग कैंप्स राष्ट्रीय स्कीम के अन्तर्गत चलते हैं उन को वहां वही स्टैंडर्ड भोजन मिलता है

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : पहलवान के लिये नहीं किया है।

श्री बूटा सिंह : पहलवानों के लिये किया है। उन्होंने ऐडीशनल चीजें मां थी, वह शायद कवर नहीं थी। इसलि

under the scheme we made special arrangements -with the help of some voluntary organisations and we were able to provide the equipment that they required. That is why . the result in our wrestling has been fantastic. We won 13 gold medals where 14 of our wrestlers participated in the internationial championship last week.

जहां तक आपने आर्चरी और तैयारी का प्रश्न किया, जैसा कि आप जानते है, जो पहलवान अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड मैडल लेकर आये उन को युवा कांग्रेस की तरफ से भी सार्वजनिक सभा में इनाम दिया गया ।

श्री इन्द्रदीप सिंह : युवा कांग्रेस क्या सरकार का अंग है ? . . . (**व्यवधान**) :

श्री बूटा सिंह : हम तो चाहते हैं आप भी दें, बी० जे० पी० वाले भी दें । लेकिन जो भी देगा उससे उनका उत्साह बढ़ेगा, इसलिये जो भी देते हैं हम उसको वेलकम करते हैं ।

आपने आर्चरी, तैराकी का वर्णन किया । यह सही है कि जो हमारे तीरन्दाज अब तक तीर कमान इस्तेमाल करते आये हैं वह दुनिया में कहीं इस्तेमाल नहीं होते । अब जो तीर कमान हैं वह बहुत मंहगे हैं, हमने एशियन गेम्स में वह तीर कमान इंपोर्ट किये और पहली बार उन्होंने उनका इस्तेमाल किया । इससे पहले जब कभी वे बाहर जाते थे तो उनको दूसरे मुल्कों से लेकर इस्तेमाल करना पड़ता था । पहली बार हमने वहां पर यह इंट्रोड्यूस की और हमारी आर्चरी की जो परफार्मेंस थी, हमें उतनी उम्मीद नहीं थी, फिर भी वह अच्छी ही । हमारे आदिवासी क्षेत्रों में यदि पोर्टेड तीर कमान उनको उपलब्ध किये जाएं तो हमारे तीरन्दाज भी नाम कमा सकते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के लिये अच्छा नाम पैदा कर सकते हैं । तैराकी के बारे में अभी यह मुस्किल होगा कि रूरल एरियाज में हम यहां की तरह स्विमिंग पूल दे सकें ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : नदी, तालाब, समुद्र तीनों यहां है ।

श्री बूटा सिंह : जैसा माननीय सदस्य ने कहा इस वक्त जो उपलब्ध साधन हमारे पास हैं उनमें जरूरत इस बात की है कि उनको अच्छे कोचेज दिये जायें जो लेटस्ट तकनीक सिखायें ताकि वह अपने रूरल क्षेत्रों में भी, नदियों में, झीलों में तैराकी कर सकें । इस वक्त जो नशनल इंस्टीट्यूट आफ स्पोर्टस पटियाला है आज तक 1961 तक से लेकर उन्होंने 5850 कोच तैयार किए है जो क्वालीफाइड कोचेज है । यह भी जो संख्या हैं हमारे राष्ट्र की विशालता को देखते हुए बहुत कम है ।

सभापति जी, में आपको बताना चाहूंगा कि जी० डी० आर० जोकि साइज में बहुत छोटा देश है वहां पर आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि जिसकी आबादी 1.7 करोड़ की है उसके पास इस समय 96 हजार कोचेज हैं जब कि हमारे पास, जिसकी आबादी दुनिया में पांचवा हिस्सा है, वहां केवल 5850 कोचेज हैं । यदि हमें साधन उपलब्ध होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक कोचेज उपलब्ध कराये जायें, खासतौर से जो दिल्ली एरियाज है, ट्राइबल बेल्ट्स हैं जिनकी तर्जेजान एक तरह से स्पोर्ट्स की है वहां पर उनको कोचेज देकर तकनीक बताई जायें ताकि वह अच्छे स्पोर्टमैन तैयार कर सकें ।

श्रीमती प्रेमिलाबाई दाजीसाहेब चव्हाण : सभापति महोदय, भारत में महाराष्ट्र ने स्पोर्टस के बारे में बहुत ही नाम कमाया है । आप सभी जानते

हैं कि जब से बूटा सिंह जी ने स्पोर्ट का महकमा संभाला है, वह बधाई देने योग्य हैं, उन्होंने सभी तरह से ध्यान रखकर जो भी कोशिश की है उससे काफी काम हुआ है और आप लोगों की सहायता से उनको काफी सराहना मिल रही है । सबसे शुभ बात यह है कि हमारे लोगों ने इंटरनेशनल अवार्ड लिया है क्रिकेट का, तब से हौंसला और भी बढ़ा है और यह आवश्यकता पैदा हुई है कि स्पोर्ट्स के बारे में जितनी भी सहायता देनी होगी वह नेशनल तौर पर देनी होगी । तो यह जो रूरल के बारे में सुझाव आया है कि ज्यादा ध्यान उधर देना चाहिये । अच्छा सुझाव है ताकि रूरल एरियाज से बहुत अच्छे स्पोर्टसमन कुश्ती में, कब्बड़ी में, खो खो में निकलते हैं मशहूर होते हैं दुनिया भर में उसी तरह से दूसरे खेलों में भी अच्छे खिलाड़ी निकल सकें । मैं जिस गांव से आती हूं कराड से, वहां एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है । इस स्टेडियम का एथलीट्स भी फायदा उठाते हैं । ऐसी जगह रूरल एरियाज में भी बनानी चाहिये ताकि वहां के लोगों को बढ़ावा मिले । इसके साथ-साथ ही खाने पीने की जो भी सुविधा है खिलाड़ियों को अपनी सेहत बढ़ाने के लिये देना चाहिये । मैं समझती हूं इससे वे और अच्छे बनेंगे । हमारे वहां कबड्डी खो-खो, बास्केट बाल, हाकी, फुटबाल, स्वीमिंग के खिलाड़ी भी फायदा उठा सकते है लेकिन कमी सिर्फ फंड की है । मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगी कि इनको स्टेट गवर्नमेंट को यह कहना चाहिये कि वे अपना ज्यादातर ध्यान ग्रामीण भागों में लगाये अपना फंड भी ज्यादातर वहां खर्च करें । इससे उनको सहूलियत और फसिलिटीज देनी होगी ताकि उनकी देखभाल अच्छी तरह से हो सकती है । स्कूल और कालेज में भी जहां खिलाड़ी पैदा होते हैं वहां भी फैसिलिटीज बढ़ानी होगी । अगर वहां उनको यह सुविधा दी जायेगी तो इससे देश का नाम रोशन वे कर पायेंगे । राष्ट्र को मजबूत और सुदृढ़ बनाने के लिए यह भी आवश्यक है । मैं मंत्री महोदय से कहूंगी कि आप इस बारे में जो कोशिश कर रहे हैं उस से हम सब सहमत है । नेशनल स्पोर्टस ट्रेनिंग के बारे में जैसा अभी आपने बताया कि एक पटियाला में है, मैं कहना चाहती हूं कि ऐसा ही एक दक्षिण भारत में भी होना चाहिये ताकि अच्छे कोचेज तैयार हो । मैं बधाई देना चाहती हूं मंत्री महोदय को कि आज अखबार में निकला कि अच्छे कोचेस अपने देश में तब जगह देने के लिये कोशिश हो रही है (**व्यवधान**) मैं जानना चाहती हूं कि क्या मंत्री महोदय इस बात की कोशिश करेंगे कि पटियाला में जिस तरह से ट्रेनिंग सेन्टर खोला हुआ है उसी तरह से दूसरी जगहों पर भी खोले जायेंगे ?

श्री बूटा सिंह : सभापति जी, मैं माननीय सदस्या का आभारी हूं कि राष्ट्र में खेल कूद में नई जागृति पैदा हुई और नवम एशियाई खेलों की वजह से बच्चों में दिलचस्पी पैदा हुई और हमारे खिलाड़ियों का जो इससे होसला बढ़ा है, इसकी जो उन्होंने सराहना की है इसके लिए मैं उनका आभारी हूं । माननीय सदस्या ने महाराष्ट्र के खिलाड़ियों का उल्लेख किया । इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जितने भी राष्ट्रीय टीम में खिलाड़ी होते है उसमें महाराष्ट्र का बहुत ज्यादा हिस्सा रहता है । महाराष्ट्र ने बहुत अच्छे खिलाड़ी पैदा किये हैं । जहां तक पहलवानों की बात है , कोल्हापुर के पहलवान सारी दुनिया में मशहूर हैं । महाराष्ट्र का योगदान हमारे स्पोर्टस में बहुत ज्यादा

है । आपने कराड के स्टेडियम की बात कही है । माननीय सदस्या से मैं अनुरोध करूंगा कि यदि वह मुझे एक विवरण डिटेल में लिख कर दे दें कि उसमें क्या सहायता हो सकती है तो हम उसकी कोशिश करेंगे ।

आपने फर्माया कि सिर्फ एक ही राष्ट्रीय संस्थान है पटियाला में । यह बात सही नहीं है । इस वक्त दक्षिण में भी हमारा एक संस्थान है, बंगलोर में और एक पूर्व में कलकत्ता में अभी हमारे राष्ट्रपति महोदय ने खोला है । इसी प्रकार से तीन हमारे देश में चल रहे हैं। सब-सेन्टर्स तो बहुत से है रीजन्स में जहां कोचिंग फेसिलिटीज दी जाती है मैं ऐसा भी सोचता हूं कि इस तरह के सेन्टर्स, जैसा पटियाला में है, बंगलौर में है, कलकत्ता में है और गोहाटी में खोलने के लिए भी हमारे पास एक पत्र आया है तो इस तरह से बहुत से सेन्टर्स हों ताकि ट्रेनिंग कोचिंग डिसेन्ट्रलाइज हो । यह सुविधा सभी लोगों को उपलब्ध हो सके । क्वालीफाइड कोचेज की तरफ भी सरकार का ध्यान है ।

SHRI SANKAR PRASAD MITRA: At page 3 of his statement, the Hon'ble Minister has said that in 22 years 5.830 professional coaches in different .disciplines have been trained. May, I know what these disciplines are and how many of them are indigenous disciplines?

श्री बूटा सिंह : इस वक्त जो कोचिंग पटियाला में है वह तकरीबन तकरीबन सभी खेलों में है । इंडिजिनस आप किस को कहते है, पता नहीं । They do not belong to any particular country. But, Sir, there are indigenous games of India.

जैसा कि माननीय सदस्य ने शुरू में कहा कि खो खो, कबड्डी और रेस्लिंग इस तरह के खेल है ।

श्री सभापति : कबड्डी तो अपना गैम है । यह आस्ट्रेलिया में कहां चलता है?

श्री बूटा सिंह : बाहर की छः कन्ट्रीज है जहां पर यह चलती है । नेपाल में खेली जा रही है, श्रीलंका में खेली जा रही है, मलेशिया में खेली जा रही है, सिंगापुर में खेली जा रही है। यह भारतीय खेल है जो दूसरे देशों में खेला जा रहा है । ये चार पांच खेल हैं जिनका वर्णन मैंने प्रश्नकर्ता के उत्तर में किया है । इसके अलावा पटियाला इंस्टिट्यूट में हम कोचिंग फैसिलिटीज देते हैं और कोचेज भी उपलब्ध कराते हैं । बहुत से खेल हैं जिनको हम इंडियन गेम्स मानते हैं । हम तो हाकी को भी इंडियन गैम ही मानते है । इस तरह से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी खेल है उनके लिए अच्छे कोचेज उपलब्ध हों उसके लिए पटियाला में प्रावधान किया गया है । The Patiala Institute is a recognwed Institute and it is recognised not only in India, but also throughout Che world. People from other countries come there to get special training and we are very proud of the Patiala Institute.

श्री मिर्जा इरशादबेग एयूबबेग : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि हमारी भारतीय टीम ने विश्व में नाम कमाया है, लेकिन विश्व में और भी दूसरी स्पर्धाएं होती है जिनमें भारतीय टीम अच्छा कौशल दिखा सकती है । लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे जो स्पोर्टस मेन है उनकी तरफ जितनी तवज्जह दी जानी चाहिए उतनी तवज्जह नही दी जाती है । हमारे देश में ऐसे अच्छे

स्पोर्ट्समैन हैं जो विश्व की कक्षा में आकर अपने खेल को अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर स्पोर्ट्स-मैन चूंकि किसी फर्म में काम करते है या किसी बैंक में इम्पलाईड हैं या किसी दूसरी जगह पर इम्पलाईड हैं, उनका पूरा समय खेल की तरफ नहीं जाता है। ऐसी हालत में मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ऐसे चुने हुए खिलाडियों के लिए क्या आप कोई स्पेशल प्रावधान करना चाहते हैं जिससे वे अपना सम्पूर्ण समय खेलों पर लगा सकें, ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरिएन्स प्राप्त कर सकें? म यह भी जानना चाहता हूं कि क्या विदेशों से स्पेशल कोचेज आयात करके खिलाड़ियों को स्पेशल ट्रैनिंग देने के लिए आपके पास कोई आयोजन है। इसके साथ साथ में यह भी जानना चाहता हूं कि क्या आप राज्यों—चूंकि एजूकेशन राज्यों का विषय है—उनसे कहेंगे कि हर राज्य में ऐसी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए वहां पर कोई डिप्लोमा कोर्स या डिग्री कोर्स होना चाहिए और क्या इस प्रकार का कोई आयोजन आपके मंत्रालय की तरफ से हो रहा है?

श्री बूटा सिंह : सभापति जी, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, यह तो सचमुच में सभी के लिए चिन्ता का विषय है कि हमारे खिलाड़ी जब अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जाते है तो वे उतना ज्यादा अच्छा नहीं करते है जितना दूसरे देशों के खिलाड़ी करते हैं। इसके लिए तो पूरे राष्ट्र को चिन्ता करनी चाहिए क्योंकि यह सिर्फ एक राज्य का प्रश्न नहीं है। इस वक्त जो परिस्थिति है वह यह है कि स्पोर्ट्स जो है वे स्टेट सबजेक्ट है। हम तो यहां से थोड़ी बहुत डाय-रेक्शन दे सकते हैं, गाइडलाइन्स दे सकते हैं, एनेबलिंग फेसिलिटीज दे सकते है, लेकिन ब्रिडिंग सेलेक्शन ट्रैनिंग और उनकी नारिसिंग स्टेट्स में होती है। सदन यह भी जानना चाहेगा कि जो हमारे खिलाड़ी बाहर जाते है वे न केवल राज्यों के प्रतिनिधि होते है बल्कि हमारे यहां कुछ स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड्स है जिनका योगदान भी इसमें बहुत होता है। राज्यों के अलावा सर्विसेज स्पोर्टस कंट्रोल बोर्ड है, रेलवे सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है, पी० एण्ड टी० स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है, पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है और इसी तरह से एयरलाइन्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है और मेजर पोर्ट्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है। ये सब बड़े बड़ संस्थान है जो बहुत साधन सम्पन्न है। उनके पास अवसर है और साधन भी हैं। वे भी इस दिशा में काफी काम करते हैं। यदि सिस्टम के ऊपर ही हमें रहना हो तो इस वक्त राज्यों के माध्यम से हम जो कुछ कर रहें है उसमें मैं समझता हूं कि शायद एक भी खिलाड़ी बाहर न जाने पायें। इसलिए पूरे राष्ट्र को, जितने भी हमारे देश में संगठन है उन सब को साधन जुटाने होंगे और हमारे स्पोर्ट्समैन को प्रश्रय देना होगा। होता क्या है कि हमारे देश में स्पोर्ट्समैन को हम उस वक्त पकड़ते हैं जब वह 20 साल का हो जाता है, कहीं पर नौकरी पा जाता है। उसको उस्र वक्त पकड़ना चाहिए जब उसकी उम्र 10-12 वर्ष की हो। बाहर के देशों में यही किया जाता है। हमारे देश में पहले उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। जब वह कालेज या युनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है और जब वह स्टेट का चैम्पीयन हो जाता है। उससे पहले कैसे उसकी परवरिश होती है, कैसे उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है इट इज नो बडीज बिजनेस।

श्री जे० के० जैन : बहुत से मुल्कों में 6-7 की उम्र से ले लिये जाते हैं

श्री बूटा सिंह : हमारे खिलाड़ियों को उस वक्त रिकग्नाइज्ड किया जाता है कि जब वे डबल ग्रेजुएशन करके नौकरी में जाते हैं, टाटा के पास, इंडियन एयरलाइन्स के पास, रेलवे के पास, तब जाकर राष्ट्र उनको रिकग्नाइज्ड करता है उसके लिये मुश्किल से एक या दो साल बाकी बचते है । जब कि एक खिलाड़ी को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पार ले जाने के लिये कम से कम दस साल चाहिएं । चाहे आप वेस्ट जर्मनी का प्रश्न ले लें या जी० डी० आर० का प्रश्न लें लें । जी० डी० आर एक बहुत छोटा सा देश है जो कि आज दुनिया के बड़े बड़े देशों के मुकाबले में आगे निकल रहा है । क्यों निकल रहा है इतना आगे खेल कूद के मैदान में? 1976 में उन्होंने खेलकूद के मैदान में इंटर किया और आज आठ साल में वे लोग दुनिया के चैम्पियन बन गये हैं । इसलिये कि वहां एक योजनाबद्ध ढंग से एक सिस्टम के माध्यम से

श्री सभापति : आपने बताया इतनी आबादी है और 96 हजार ... **(व्यवधान)** ... आपके पास 5 हजार है ... **(व्यवधान)** ...

श्री बूटा सिंह : वहां 96 हजार हैं । इसलिये हमने एक नेशनल स्पोर्ट्स पालिसी का निर्माण किया है वह स्पोर्ट्स पालिसी डिसकस होगी । दुख इस बात का है कि यह सबजेक्ट स्टेट सबजेक्ट है यदि यह कान्करेन्ट सब्जेक्ट होता तो हम सब स्टेट्स को साथ लेकर इसके लिये कुछ करते । फिर भी एक शुरुआत हुई है और एक नेशनल पालिसी इवाल्व हुई है । इस नेशनल पालिसी को सभी राज्यों से डिसकस करके सदन के सामने लाया जायेगा और सदन की राय लेकर सदन की स्वीकृति लेकर इसके ऊपर कार्यवाही करेंगे और फिर हम उम्मीद करते है कि कोई टाइम बाउन्ड प्रोग्राम बनाकर, दस साल का, पांच साल का इसको करेंगे । सैलेक्टिव स्पोर्ट्स के बारे में हमारी बातचीत इंडियन ओलम्पिक एसोसियेशन से और आल इंडिया कौंसिल आफ स्पोर्ट्स से हुई है और इन लोगों ने एक टाइम बाउन्ड प्रोग्राम रखने और सेलेक्टिव बेसिस पर कि किस-किस स्पोर्ट्स में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हम अपना नाम पैदा कर सकते हैं, इसके लिये उन्होंने आठ-नौ खेलों का उल्लेख किया है हम बड़ी गंभीरता के साथ उस पर सोच रहे हैं कि कैसे इन आठ-नौ खेलों में अपने खिलाड़ियों का यहां चयन करके, सेलेक्शन करके उनको देश के अंदर तैयार करें और फिर उसके बाद उनको विदेशों में ले जाकर अच्छे अच्छे कोचेज, अच्छे अच्छे एक्विपमेन्ट देकर, अच्छी खुराक देकर, पाँच साल का पीरियड देकर हम ऐसा कर रहे है ताकि इस ओलम्पिक में नहीं तो कम से कम अगले ओलम्पिक में भारतवर्ष के खिलाड़ी भी पदक प्राप्त कर सकें । इस प्रकार की योजना बनाकर हम यह कोशिश कर रहे हैं ।

श्री रामेश्वर सिंह : महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है ... **(व्यवधान)** ...

श्री रामचन्द्र भारद्वाज : श्रीमन, यह क्वेश्चन आवर है या ... **(व्यवधान)** ...

श्री बिठ्ठलराव माधवराव जाधव : श्रीमन्, मंत्री महोदय ने जी० डी० आर० का जिक्र किया है। जी० डी० आर० एक बहुत छोटा देश है और उसकी तुलना में भारत एक बहुत बड़ा देश है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जी० डी० आर० अपने स्पोर्ट्स पर कितना पैसा खर्च करता है और भारत इसमें कितना पैसा खर्च करता है ?

दूसरा मैं यह जानना चाहूंगा कि देहातों में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। ट्राइबल एरियाज में भी अच्छे-अच्छे खिलाड़ी है। तो क्या गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी योजना है कि जो अच्छे-अच्छे ट्राइबल्स खिलाड़ी हैं उनको कोच करके उनको ट्रैनिंग दे और फिजीकल एजूकेशन उनको दे ताकि जो देहातों में खिलाड़ी है, जो ट्राइबल्स खिलाड़ी हैं वे आगे आकर देश का नाम कर सकें।

श्री सभापति : वह सब हो गया है। आप कहां थे ? ये सब सवालात हो चुके हैं और जवाब भी हो चुका है, सब कुछ हो गया है।

SHRl SYED SIBTEY RAZI: Have -a Half-an-hour discussion on this subject.

SHRI BUTA SINGH: Sir, I welcome this. Let there be half-an-hour discussion on this.

MR. CHAIRMAN: If you want to know my opinion, I think our Sports are in very good hands—if you only appreciate it. You will find that it is ... (Inteiruptions)

PROF. SOURENDRA BHATTA-CHARJEE: I have a point of order, which I would like you to hear. *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Wait a minute. There is time for everything. The Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Abolition of Public School System

*444. SHRI J. P. GOYAL:
SHRI RAMCHANDRA BHARADWAJ:

Will the Minister of EDUCATION AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal •under Government's consideration to abolish public schools system in the country;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) if not, the reasons for which Government propose to continue public schools system in the country ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF EDUCATION AND CULTURE AND SOCIAL WELFARE (SHRIMATI SHEILA KAUL): (a) to (c) Public Schools are generally meant to be those schools which are members of the Indian Public Schools' Conference, a voluntary association registered as a *society* under the societies' Registration Act, 1860. According to available information, there are at present 54 such schools throughout th^ country. Education Ministry has no control over these schools, nor is it giving any grant to any of these public schools.

The question of abolition of public schools was examined some time back and the legal opinion tendered to the Government was to the effect that any action to abolish public schools will be violative of Article 30(1) of _ the Contitution in so far as public schools managed by minorities are concerned, and would be violative of Article 19(1) (g) of the Constitution in so far as non-minority public schools are concerned.

Training of Rural Youth for Self. employment

*445. SHRI JAGANNATHRAO JOSHI: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the State-wise break up of funds allotted for Trysem in 1980-81, 1981-82 and 1982-83;

(b) the number of youths proposed to be trained under this scheme in each State;

(c) the number of those actually trained in each State in each year mentioned in part (a) above;